Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

भारतीय राजनीती और इंदिरा गांधी

डॉ. शरद कौतिक भामरे, इतिहास विभाग, भाऊसाहेब ना. स. पाटील साहित्य एवं, मु. फि. मु. अ. वाणिज्य महाविद्यालय, देवपूर, धुले

सारांश

भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और अपने दृढ़ नेतृत्व, आर्थिक नीतियों, और सख्त निर्णयों के लिए जानी जाती हैं। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थीं और उन्होंने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भारत खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करने और गरीबों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ देने के लिए उन्होंने 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत के बाद 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए 1974 में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया।

1975 से 1977 में उन्होंने आपातकाल घोषित किया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाया गया और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। पंजाब में अलगाववादी आंदोलन को कुचलने के लिए स्वर्ण मंदिर में 1984 में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' नामक ऑपरेशन कर सैन्य कार्रवाई की गई, जिससे सिख समुदाय में असंतोष बढ़ा। जिसकारण 31 अक्टूबर, 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। उनकी राजनीतिक विरासत आज भी भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इंदिरा गांधी का शासनकाल भारतीय राजनीति में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वे एक सशक्त नेता थीं, जिन्होंने भारत की दिशा को बदलने वाले कई बड़े फैसले लिए।

मुख्य संबोध

महिला प्रधानमंत्री, भारतीय राजनीति, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परमाणु शक्ति, परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति, ऑपरेशन ब्लू स्टार, अलगाववादी, आंदोलन, आपातकाल, राजनीतिक विरासत।

विषय प्रवेश

इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर, 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थीं। उनकी शिक्षा शांति निकेतन, ऑक्सफोर्ड और स्विट्जरलैंड के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में हुई। बचपन से ही वे स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित रहीं और उन्होंने राजनीति में गहरी रुचि ली।

तीन मूर्ति भवन की तुलना में नये घर में जीवन की व्यवस्था बहुत भिन्न थी, लेकिन एक नियम बना रहा-प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे तक इन्दिरा गाँधी के निवास-स्थान के द्वार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए खुले रहते थे। उनमें राजनीतिज्ञ और सार्वजनिक हस्तियाँ, मजदूर और किसान, छात्र और पर्यटक -सभी होते थे। कुछ लोग राज-काज के सम्बन्ध में उनसे मिलते थे, कुछ अन्य आवेदन-पत्रों और शिकायतों के साथ

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

अथवा उनकी राय लेने के लिए, तो कुछ सिर्फ उनके दर्शन के लिए आते थे। सफदरजंग रोड के इस बैंगले पर सुबह जमा होने वाली भीड़ से यह स्पष्ट हो जाता था कि इसमें निवास करने वाली हस्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि नामी राजनीतिज्ञ थी, जिसे जनता अपनी नेता मानती थी।

सत्ताधारी पार्टी का नेतृत्व नेहरू का उत्तराधिकारी चुनने का कठिन मसला हल कर रहा था। जैसा कि अनुमान था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बने और इन्दिरा को भी अपनी इच्छा बताई, ताकि उनका महत्त्वपूर्ण. समर्थन मिल सके। पर इन्दिरा गाँधी ने साफ-साफ बताया कि वह लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में मतदान करेंगी। और जब सरकार के प्रधान का पद स्वयं इन्दिरा गाँधी को सौंपने की पेशकश की गई, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को फौरन नामंजूर कर दिया। कांग्रेस के एक पुराने 'दिग्गज' के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ने का उनका कोई इरादा नहीं था। शास्त्रीजी ने आग्रह किया कि वह उनके मन्त्रिमण्डल में शामिल हो जाए। थोड़े संकोच के बाद इन्दिरा गाँधी ने सूचना तथा प्रसारण मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। अगस्त, 1964 में वह पहली बार भारतीय संसद के लिए निर्वाचित हुई।

उन दिनों सोशलिस्ट कांग्रेसमैन समाचारपत्र में 'इन्दिराजी की नयी भूमिका' शीर्षक सम्पादकीय में लिखा गया था "जनता नेहरूजी के प्रति केवल इसलिए आभारी नहीं है कि उन्होंने भारत की महत्त्वपूर्ण सेवा की थी, बल्कि इसलिए भी कि वह अपने प्रतीक के रूप में अपने पीछे इन्दिरा गाँधी को छोड़ गए।"[1]

"वह सम्मान के योग्य और राष्ट्र की आशा हैं," लेख में कहा गया। "नये मन्त्रिमण्डल में उनके शामिल होने का अर्थ यह है कि सरकार नेहरू की नीति चलाएगी। शास्त्रीजी तथा नन्दाजी के साथ वह इस बात की गारण्टी हैं कि नेहरू की नीति जारी रखी जाएगी और भारत समाजवादी लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्ग से नहीं भटकेगा।"[2]

मंत्री पद स्वीकार करके इन्दिरा गाँधी को यह मंजूर नहीं था कि नेहरू की नीति में अप्रत्यक्ष हेर-फेर के उद्देश्य से उन्हें परदे के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कई बार शास्त्रीजी के सामने इस पर नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के दक्षिणपंथी 'आकाओं' की राजनीतिक चालों में शामिल न होते हुए और खुलकर उनकी उपेक्षा करते हुए इन्दिरा कांग्रेस के आम सदस्यों, जनसाधारण को सम्बोधित करती रहीं।

भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण, जो कश्मीर को लेकर छिड़ा था, देश की स्थिति जटिल हो गई थी। उस समय इन्दिरा गाँधी स्वयं कई बार युद्ध-क्षेत्र में पहुँची थीं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी अडिगता का परिचय दिया। उन्होंने रक्षा योजना का बारीकी के साथ अध्ययन किया, अग्रिम अड्डों का निरीक्षण किया और अपने जीवन को खतरे में डालकर फौजी हेलिकाप्टर से युद्ध-स्थल का सर्वेक्षण किया। सोवियत सरकार की मध्यस्थता से आयोजित ताशकन्द में हुए भारतीय-पाकिस्तानी सम्मेलन के फलस्वरूप दो देशों में सुलह हुई और कश्मीर में युद्ध समाप्त हो गया। ताशकन्द घोषणापत्र पर हस्ताक्षर के कुछ ही घण्टे बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के कारण शास्त्रीजी का देहान्त हो गया। इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री के निर्वाचन का प्रश्न सामने आया। इस बार मोरारजी देसाई ने इस पद के लिए उम्मीदवार बनने वाले किसी को भी चुनौती देने का निश्चय किया।

इन्दिरा गाँधी की आयु 48 वर्ष थी। सुडौल शरीर, सुन्दर नाक-नक्श, सजीव आँखें, जिनमें बुद्धिमत्ता टपक रही थी, मन-मोहक मुस्कान वह भारतीय नारी सुलभगरिमा की साक्षात् प्रतिमा थीं। इन्दिरा गाँधी को देखते ही लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई के वर्षों की तरह 'इन्कलाब जिन्दाबाद !' नारा बुलन्द किया। यह उमंग भरी मुलाकात देखने वाले हर व्यक्ति के लिए साफ था कि इन्दिरा गाँधी के नाम से जनता ने आजादी,

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

बेहतर जिन्दगी, सामाजिक न्याय के लिए अपने संघर्ष को जोड़ दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर संसद भवन के सामने इकट्ठे हुए जन-समूह का अभिवादन किया और फाटक में प्रवेश किया। बड़े शान्त भाव से वह संसद के मुख्य सभा-कक्ष में दाखिल हुईं। सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। इन्दिरा के होठों पर मुस्कान खिल उठी और उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वी मोरारजी देसाई का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। देसाई ने भी उनका अभिवादन किया और सातवीं पंक्ति की अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मतदान शुरू हुआ। महात्मा गाँधी, मोतीलाल तथा जवाहरलाल नेहरू के बड़े छविचित्रों के नीचे मतपेटी रखी हुई थी। बालकनी पर बैठे विपक्षी दलों के सदस्य और संवाददाता कांग्रेसी सांसदों को वोट देते हुए देख रहे थे। मतदान के परिणाम की प्रतीक्षा में हॉल में सन्नाटा छा गया। आखिरकार द्वार से संसदीय मामलों के मंत्री निकले। उसी क्षण किसी सांसद के मुँह से सहसा निकला- "लड़का या लड़की?" मंत्रीजी मुस्कराए, बोले- "लड़की!"[3] और इसके बाद गम्भीर आवाज में मतदान में वोटों की गिनती की अधिकृत घोषणा सुनाई- "श्रीमती इन्दिरा गाँधी की जीत हुई है। उन्हें 355 वोट प्राप्त हुए हैं और श्री मोरारजी देसाई को 169 बोट ।"[4] नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पर फूलों की बौछार की गई।

श्रीमती गाँधी ने अत्यन्त जटिल आन्तरिक तथा विदेशी समस्याओं में उलझे विशाल देश के शासन-संचालन की जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके पीछे उनका व्यक्तिगत मिथ्याभिमान नहीं था और न सम्मान और सत्ता पाने की भूख थी। पर न ही वह नाममात्र की प्रधानमंत्री बनना चाहती थीं, 'सिंडिकेट' द्वारा उनके लिए पूर्वनिश्चित यह भूमिका उन्हें कतई मंजूर नहीं थी। वह राष्ट्र की सच्ची नेता बनना चाहती थीं और प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष शुरू करते हुए उन्होंने देशभक्तिपूर्ण लक्ष्य अपने सामने रखा। उनके पास स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम था। अपने लक्ष्य का स्पष्टीकरण करते हुए इन्दिरा गाँधी ने कहा- "श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की सम्भावना से मैं इसलिए चिन्तित थी कि उनकी नीति हमारे प्रयासों के सर्वथा प्रतिकूल थी और मुझे डर था कि भारत फौरन ही अपनी नीति की दिशा बदल देगा।"[5]

श्रीमती गाँधी को अनेक ज्वलन्त समस्याओं को हल करना था, जिनमें घोर खाद्य संकट से देश को उबारना प्रमुख था। सरकार की विदेश नीति की ओर भी उचित ध्यान देना जरूरी था। नये भारत के निर्माण की सफलता अन्ततः युद्ध और शान्ति की समस्याओं के समाधान पर, पराधीन देशों के स्वतन्त्र होते जाने की प्रक्रिया पर, राज्यों के बीच सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव-शैथिल्य पर निर्भर करती थी। यदि भिन्न सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति असफल होगी, तो भारत की सारी शान्ति-योजनाएँ विफल हो जाएँगी और उसे भीतरी तथा बाहरी प्रतिक्रियावादी तत्त्वों के सामने पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी यही नेहरूजी का विश्वास था और इन्दिरा गाँधी भी इसी निष्कर्ष पर पहुँची थीं। यह नहीं होने दिया जा सकता था।

इन्दिरा गाँधी की मास्को यात्रा बहुत सफल रही-द्विपक्षीय सम्बन्धों के व्यावहारिक प्रश्नों के हल से दोनों पक्षों को सन्तोष हुआ, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर लाभदायक विचार-विनिमय हुआ। इन्दिरा गाँधी उन गिने-चुने राजनीतिज्ञों में थीं, जो किसी राजनीतिक षड्यन्त्र के परिणामस्वरूप अथवा संयोगवश सत्ता की ऊँचाई पर नहीं पहुँचते। उनका चयन स्वयं इतिहास द्वारा, अपने जनगण के सच्चे नेताओं के रूप में किया जाता है। ऐसे नेताओं की विशिष्टता यह होती है कि वे जनता का सहारा लेते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय कार्य तथा राजनयिक गतिविधियाँ सरकारों का विशेषाधिकार

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

नहीं रह गए हैं। जनगण राजनीतिक संघर्षों में अधिकाधिक सक्रिय होते जा रहे हैं और वे दुनिया की स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष सूचना पाना चाहते हैं।

सोवियत टेलीविजन पर अपने भाषण में इन्दिरा गाँधी ने कहा- "हमारी विदेश नीति गुटनिरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों पर आधारित है। ये सिद्धान्त विकासमान देशों की स्वाधीनता और अखण्डता की सर्वोत्तम गारण्टी हैं। सोवियत संघ तथा दूसरे मित्र देशों के साथ हमारे सम्बन्ध गुटनिरपेक्षता की नीति को सुदृढ़ बनाने में सहायक हैं। यह निष्क्रिय नहीं, वरन् सक्रिय नीति है। "युद्ध और मानव दुखों की समस्या हमें बहुत चिन्तित करती है और आज हम वियतनाम की परिस्थिति के शान्तिपूर्ण नियमन के लिए अपील में अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं। हमारी पूरी सहानुभूति साहसी वियतनामी जनता के साथ है...।"[6] नस्लवाद तथा उपनिवेशवाद की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण, पूर्ण निरस्त्रीकरण कराने की हमारी इच्छा, अमीर और गरीब देशों के बीच खतरनाक रूप से बढ़ती हुई खाई को पाटने की हमारी अभिलाषा सुविदित है।

"इन और दूसरे मुद्दों पर सोवियत संघ और भारत के दृष्टिकोण बहुत हद तक मिलते-जुलते हैं। मन्त्रिपरिषद् के अध्यक्ष श्री कोसीगिन तथा उनके साथियों के साथ मेरी वार्ताएँ लाभदायक रहीं। भारत-सोवियत मैत्री का स्नेहमय प्रकाश मैं अपने साथ लेती जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि सोवियत संघ के रूप में हमें अच्छा मित्र प्राप्त हुआ है और मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता भी आपकी निष्ठावान मित्र है। यह मैत्री मात्र एक वास्तविकता नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।"[7]

नेहरूजी की मृत्यु के बाद पहली बार 1967 में भारत में चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी फिर विजयी हुई, लेकिन बड़ी कठिनाई से और उसे नुकसान भी उठाने पड़े। विपक्षी दलों ने संसद में अपनी स्थिति मजबूत बना ली और पाँच राज्यों में वे सत्ता में आ गए, जहाँ उन्होंने गैरकांग्रेसी सरकारें बनाई। इन्दिरा गाँधी इसके लिए जिम्मेदार नहीं थीं-भारतीय तथा विदेशी पर्यवेक्षकों का यह समान निष्कर्ष था। स्वयं उन्हें चुनावों में निर्विवाद विजय मिली थी। चुनाव के निराशाजनक परिणाम एक और ही बात की ओर-जनता के बीच सत्ताधारी पार्टी की घटती हुई प्रतिष्ठा की ओर संकेत कर रहे थे।

सोवियत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए इन्दिरा गाँधी ने बताया कि "अनेक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर कांग्रेस में मतभेद हैं। इन समस्याओं को लेकर नेहरू की नीति में विश्वास रखने वाले लोगों और उन लोगों के बीच संघर्ष चल रहा है, जो कथनी में तो इस नीति को स्वीकार करते हैं, परन्तु वास्तव में उसे अमल में लाने न देने के लिए हरचंद कोशिश करते रहे हैं। नेहरू की नीति के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच टक्करें नेहरूजी के जीवन काल में ही शुरू हो गई थीं। लेकिन उस समय नेहरू के विरोधी खुलेआम सामने आने का साहस नहीं करते थे, वे गुप्त रूप से पार्टी की नीति को नाकाम करने की कोशिश करते थे... इसलिए आज जो कुछ हो रहा है, यह कोई नयी प्रवृत्ति नहीं, वरन् पुराने संघर्ष तथा पुराने मतभेदों का सिलसिला है।"[8]

इन्दिरा गाँधी ने 14 सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का साहसपूर्ण फैसला किया। 'दस सूत्री कार्यक्रम' की अपेक्षा यह कहीं अधिक आमूलगामी कार्रवाई थी, क्योंकि उस कार्यक्रम में निजी बैंकों पर केवल सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करने का प्रावधान था। अपने निर्णय का स्पष्टीकरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक जीवन में नियन्त्रणकारी भूमिका अदा करने वाली बैंक व्यवस्था को सामान्य सामाजिक धारणाओं पर स्थापित होना और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अखिल राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

कार्यभारों द्वारा निर्धारित होना चाहिए। इन्दिरा गाँधी विश्वास करती थीं कि "समाजवादी नमूने के समाज" की धारणा के अनुसार अर्थतन्त्र की प्रमुख शाखाएँ राज्य की सम्पत्ति होनी चाहिए और राज्य द्वारा नियन्त्रित होनी चाहिए।

इंदिरा गांधी के कार्यो को देखते हुए विपक्षी दलों ने अपना पूरा चुनाव अभियान ही इन नारों के साथ चलाया- "रानी को गद्दी से हटाओ" और "तानाशाही का नाश हो"। अधिकांश मतदाताओं ने जनता पार्टी नामक गठजोड़ के पक्ष में मतदान किया। कांग्रेस, जो दक्षिणपंथियों द्वारा विभाजित कर दी गई थी तथा जनता के साथ जिसके सम्बन्ध कमजोर पड़ गए थे, हार गई-तीस वर्ष पहले सत्तारूढ़ बनने के बाद पहली बार। मोरारजी देसाई ने नयी सरकार बनाई।

31 अक्टूबर, 1984 को उनके अंगरक्षकों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनका बलिदान और योगदान आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास में अमिट है।

निष्कर्ष

1. इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, जिन्होंने अपने नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से देश को एक नई दिशा दी। वे न केवल भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली नेता थीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनकी छवि एक सशक्त और दूरदर्शी नेता के रूप में स्थापित हुई।
2. इंदिरा गांधी ने 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली। उनके नेतृत्व कौशल और राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण उन्हें 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। वे कुल 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहीं (1966-1977 और 1980-1984)।
3. उन्होंने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को बढ़ावा दिया, जिससे भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बना।
4. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
5. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुवा, जिससे गरीबों और किसानों को ऋण प्राप्त करने में आसानी हुई।
6. इंदिरा गांधी के नेतृत्व में में पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण कराकर देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया।
7. इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लगाया गया, जिसे उनकी सबसे विवादास्पद नीतियों में गिना जाता है।
8. इंदिरा गांधी एक सशक्त, निर्भीक और दूरदर्शी नेता थीं। उन्होंने भारत को आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक रूप से मज़बूत किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और नीतियों के कारण उन्हें "आयरन लेडी ऑफ इंडिया" कहा जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है।

संदर्भ ग्रंथ

1. इन्दिरा गाँधी, लेख, भाषण तथा भेंटवार्ताएँ, मास्को, 1975 (रूसी में)।
2. इन्दिरा गाँधी, भारत की विदेश नीति। संकलित भाषण। 1980-82, मास्को, 1982 (रूसी में)।
3. गांधी एम. के., सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1957, पृ. क्र. 68

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved

Journal of East-West Thought
ISSN: *2168-2259 (online)*
(https://jetjournal.us/)
Volume 15, Issue 1, Jan-March – 2025 Special Issue 1
Impact Factor: 7.665, Peer Reviewed and UGC CARE I

4. www.gandhi.co.in
5. इन्दिरा गाँधी, भारत की विदेश नीति। संकलित भाषण/ 190-82, मास्को, 1982 (रूसी में)।
6. www.indiragandhi.co.in
7. इन्दिरा गाँधी, लेख, भाषण तथा भेंटवार्ताएँ, मास्को, 1975 (रूसी में)।
8. www.indianprimeminister.co.in

Copyright © | JET Network, All Rights Reserved